

सामुदायिक संरक्षण

9

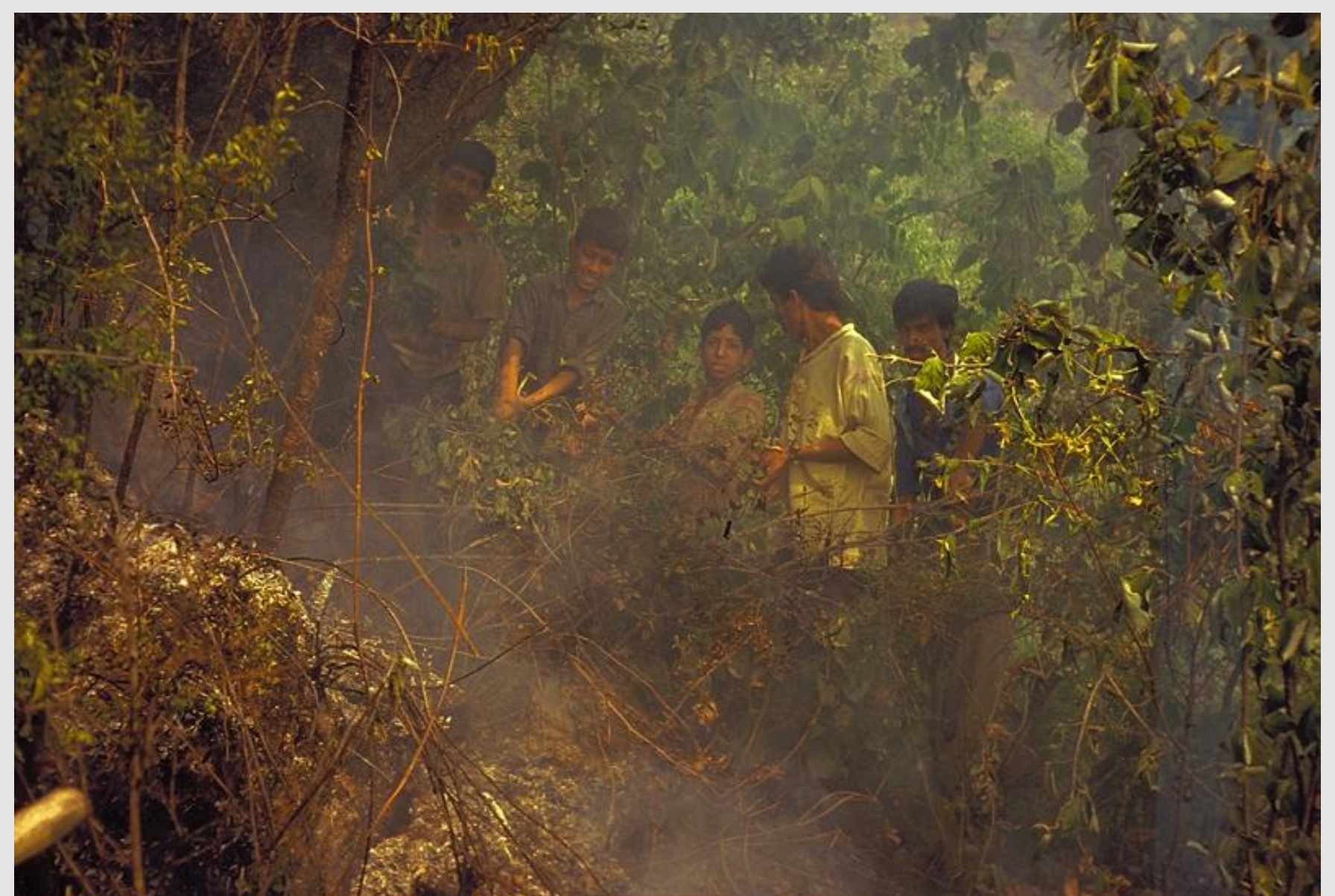
हमारे जंगल व अन्य प्राकृतिक क्षेत्र (ecosystems) करोड़ों लोगों को जीवन का आधार और आजीविका प्रदान कर रहे हैं। इनसे हमारी खेती, पशुपालन, गैर-लकड़ी वन उपज और विविध संस्कृतियों को बल व पोषण मिलता है। आज हमारे यही प्राकृतिक क्षेत्र समुदायों के भीतर और बाहर, दोनों तरफ से कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जंगलों का संरक्षण अकसर तभी कामयाब होता है जब उनका इस्तेमाल करने वाले समुदाय खुद उनके संरक्षण में भरपूर योगदान देते हों।

उत्तराखंड स्थित टिहरी गढ़वाल का **जड़धारगांव** इसका एक बढ़िया उदाहरण है। सत्तर के दशक में चले चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेकर हिमालय के निचले पहाड़ों में स्थित इस गांव के लोगों ने एक वन सुरक्षा समिति का गठन किया है ताकि लकड़ी और घास-फूस के इस्तेमाल को नियमित किया जा सके और गांव के सभी परिवारों के बीच इन संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इस समिति के सदस्य ग्राम सभा की बैठक में **आम सहमति** के आधार पर चुने जाते हैं न कि वोटों के आधार पर। चूना पत्थर की भरमार वाले इस इलाके में खनन के बाहरी खतरों से निपटने के लिए महिलाओं की समिति भी बनाई गई है।

महाराष्ट्र का **हिवरे बाजार** (नीचे) कृषि-वन समुच्चय पर आधारित एक समग्र सोच का उदाहरण है। यह सोच नशा, चरल (स्वतंत्र चराई), कुल्हड़ (पेड़ों की बेतहाशा कटाई) और नस (जनसंख्या वृद्धि) की बंदी यानी रोक पर आधारित है।



ऊपर: जड़धारगांव, उत्तराखंड में वन सुरक्षा समिति की एक बैठक का दृश्य।



ऊपर: जड़धारगांव के लोग जंगल में लगी आग बुझा रहे हैं।



ऊपर: जड़धारगांव के आसपास पुनर्जीवित किए गए जंगल।

तब



बाएं से दाएं: हिवरे बाजार, महाराष्ट्र में सामुदायिक सक्रियता के फलस्वरूप आए ऐतिहासिक बदलाव।

अब

